

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-104/2010/अजमेर.
(सम्बन्धित अपील संख्या-1724/2008/अजमेर)

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, पाली.

.....अपीलार्थी (अप्रार्थी).

बनाम

मैसर्स बीकोन स्टील्स, मण्डी गोविन्दगढ़.

.....प्रत्यर्थी (प्रार्थी).

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ. पी. माहेश्वरी, अधिकृत प्रतिनिधि

.....प्रार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,

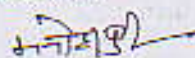
उप-राजकीय अभिगावक

.....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/9/2014

निर्णय

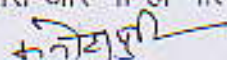
1. यह परिशोधन प्रार्थना-पत्र प्रार्थी (प्रत्यर्थी) मैसर्स बीकोन स्टील्स द्वारा राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1724/2008/अजमेर में एकलपीठ द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 27.8.2010 में परिशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 सपटित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 37 के तहत प्रस्तुत किया गया है।
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, पाली (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2000 के द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 30,000/- आरोपित की गई।
3. उक्त आदेश के विरुद्ध उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील संख्या 173/आरएसटी/एनआरडी/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2008 के द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया।
4. अपीलीय अधिकारी के आदेश पारित 05.03.2008 के विरुद्ध माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 1724/2008/अजमेर प्रस्तुत की गयी, जिसे एकलपीठ के निर्णय दिनांक 27.08.2010 के द्वारा निर्णीत किया जाकर निस्तारित किया गया। निर्णय दिनांक 27.08.2010 का पैरा संख्या 11 निम्न प्रकार है :-



"11. अतः अपीलार्थी-विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करके, उपायुक्त (अपील्स) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली उपायुक्त (अपील्स) को इस निर्देश के साथ "प्रतिप्रेषित" की जाती है कि वह उभयपक्षों को सुनकर, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वाहन चालक रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत "प्रार्थना-पत्र" व "ब्यान" तथा माल के हितबद्ध "ओमप्रकाश" के "ब्यान" व "प्रार्थना-पत्र" तथा पीठ द्वारा इस निर्णय में समीक्षा किये गये बिन्दुओं को ध्यान में रखकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध "बयानों" का विधिसम्मत अधिमूल्यन करके, प्रकरण का निर्णय फिर से करे।....."

5. प्रत्यर्थी (प्रार्थी) द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना-पत्र में लिखित Submission में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त पारित आदेश में अभिलेख से प्रकट भूल है तथा पारित आदेश अपील आधारों से परे किया गया है। अपीलीय अधिकारी को इस धारा के अधीन निर्देश देने का अधिकार नहीं है। आगे उल्लेख किया कि अधिनियम की धारा 78(5) में वाहन के मालिक पर शास्ति आरोपण का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलीय अधिकारी के अभिलेख के आधार पर माल गन्तव्य स्थान मण्डी गोविन्दगढ़ पहुंचने का उल्लेख किया गया है तथा माल का प्रवेश गुजरात राज्य से हुआ। इस प्रकार के मामलों में प्रतिकरापवंचन शाखा के अधिकारियों को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रेषिति फर्म मैसर्स बिकोन स्टील्स के द्वारा दिनांक 17.10.2000 के माल उनके होने के बारे में पुष्टि का पत्र अभिलेख में होने का उल्लेख किया है। ऐसी परिस्थिति में प्रेषक मैसर्स संजय ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन या प्रेषिति मैसर्स बिकोन स्टील्स को नोटिस जारी किया जाना चाहिये था, ना कि वाहन के मालिक को। परिपत्र संख्या 2007/704 दिनांक 17.7.2008 का भी उल्लेख किया, जिसमें अभिग्रहित माल को वाहन मालिक को नहीं सुपुर्द किया जाना चाहिये, का उल्लेख होना बताया है। इस प्रकार वाहन मालिक के खिलाफ की गई समस्त कार्यवाही विधिविरुद्ध है। इस प्रकरण में वाहन मालिक को माल मालिक होना स्वीकार किया गया है। अतिरिक्त आदेश को प्रतिप्रेषण के द्वारा विधिक नहीं किया जाना चाहिये। इस प्रकार प्रतिप्रेषण आदेश गलत है तथा यह अभिलेख से प्रकट भूल है।

6. प्रत्यर्थी (प्रार्थी) के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस के समय लिखित में उल्लेख किया, जिसके अनुसार वाहन को निरुद्ध करने का नोटिस दिनांक 14.10.2000 तथा कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.10.2000 श्री रामचन्द्र जाट वाहन चालक तथा माल प्रभारी वाहन संख्या आर.जे.01/जी-4729 को जारी किया गया है। इस प्रकार वाहन का चालक व प्रभारी श्री रामचन्द्र जाट था, ना कि वाहन मालिक श्री ओमप्रकाश, जो कि ना तो माल प्रभारी रहा, ना ही वाहन प्रभारी और ना ही माल का मालिक था।



7. शास्ति का नोटिस दिनांक 18.10.2000 मैसर्स बीकोन स्टील्स को जारी किया गया तथा शास्ति आरोपण का आदेश ओमप्रकाश वाहन मालिक के नाम पर पारित किया गया, जो अविधिक व गलत होने का उल्लेख किया। शास्ति आरोपण वाहन चालक व वाहन प्रगारी पर किया जाना चाहिये, ना कि वाहन मालिक पर।

8. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपील आधारों में न्यायिक दृष्टान्त (1997) 228 आई.टी.आर. 463 (एस.सी.), (1961) 41 आई.टी.आर. 732 (एस.सी.) व (1958) 34 आई.टी.आर. 143 (एस.सी.) उद्धरित किये तथा तथ्यों की त्रुटि व विधि की त्रुटि संशोधनीय होने का उल्लेख किया। आज्ञापक प्रावधानों को नजरअंदाज किया जाना, अभिलेख से प्रकट त्रुटि है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त (1957) आई.टी.आर. 274 Meka Venkatappaiah Vs. I.T.O. (SC) प्रस्तुत किया।

9. आगे उल्लेख किया कि धारा 37(4) के अधीन संशोधित किये जाने वाले आदेश दिनांक की 4 वर्ष समाप्ति के पश्चात कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1985 सुप्रीम कोर्ट 913 आदेश दिनांक 09.10.1964 राजस्थान राज्य बनाम कर्मचन्द थापर एण्ड ब्रदर्स का उल्लेख किया।

10. आगे उल्लेख किया कि "No notice from AA received to me till date for assessment in compliance to tax board order remanded to him."

11. प्रार्थी (प्रत्यर्थी) के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस में भी लिखित Submission में उल्लेखित तर्कों को दोहराया।

12. अपीलार्थी (अप्रार्थी) विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर बोर्ड के सन्दर्भित निर्णय का समर्थन किया तथा कथन किया कि वाहन मालिक प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में अधीनस्थ प्राधिकारी के यहां उपस्थित हुआ या नहीं हुआ तथा वहां क्या तथ्य बताये गये, यह विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नहीं बताये गये हैं तथा परिशोधन प्रार्थना-पत्र खारिज करने की प्रार्थना की। मौखिक रूप से अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस के वक्त यह कहा कि हमें अधीनस्थ प्राधिकारी के यहां से कोई नोटिस नहीं मिला है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 08.08.2012 की प्रति प्रस्तुत की।

13. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनियम की धारा 37 व राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-



Section 37- Rectification of a mistake.- (Rajasthan Sales Tax Act, 1994)

- (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under the Act may rectify *suo motu* or otherwise any order passed by him.

Explanation.- A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgement of the Supreme court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

- (2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.
- (3) Where an application under sub-section (1) is presented to the assessing authority, appellate authority or Tax Board and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.
- (4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of order sought to be rectified.
- (5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.

Section 33. Rectification of a mistake. - (Rajasthan Value Added Tax Act, 2003)

- (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under this Act may rectify *suo motu* or otherwise any order passed by him.

Explanation. - A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

- (2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.
- (3) Where an application under sub-section (1) is presented to the assessing authority and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.

Handwritten signature/initials

(4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of the order sought to be rectified.

(5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.

14. प्रत्यर्थी (प्रार्थी) द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित धारा के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किये गये तथ्य व विधिक स्थिति के क्रम में हस्तगत प्रकरण में अभिलेख से प्रकट भूल होने की स्थिति में ही उक्त धारा प्रयोग किये जाने योग्य (Exercisable) है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253] में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 37/33 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग अभिलेख से प्रकट भूल की स्थिति में ही किया जा सकता है। समस्त अभिलेख का पुनर्मूल्यांकन इस धारा के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records.

19. Thus, the order passed by the Taxation Board on 22.1.2009 as also the impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored."

15. प्रकरण के विवाद्य विषय में प्रत्यर्थी (प्रार्थी) द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त, जो पैरा 8 में वर्णित हैं, सुसंगतता के अभाव में उनको कोई मदद प्रदान नहीं करते हैं।

16. समय-सीमा सम्बन्धी आपत्ति के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त (1994) 92 एस.टी.सी. 578 (कर्नाटक) बाबा एसोसियेट्स बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :-

2014

"Held, dismissing the revision petition, (i) that the period of five years laid down in section 22(6-A) of the Karnataka Sales Tax Act for amending an order only contemplates moving the Tribunal within five years from the date of the order of which rectification is sought. Section 22(6-A) cannot be read to mean that the rectification order should also be passed by the Tribunal within five years. Therefore, the rectification application having been moved within the permissible period of five years, merely because the Tribunal took time to decide the same after hearing the parties and by the time the final order was passed five years' time had passed, the rectification proceedings could not be said to be barred or without jurisdiction."

17. संशोधन प्रार्थना-पत्र की समय-सीमा के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी (प्रार्थी) का तर्क उपरोक्त पैरा संख्या 16 में वर्णित माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय (1994) 92 एस.टी.सी. 578 (कर्नाटक) के आलोक में खारिज किया जाता है। प्रत्यर्थी (प्रार्थी) द्वारा उल्लेखित न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 913 प्रकरण के विवाद्य विषय में सुसंगतता के अभाव में कोई मदद प्रदान नहीं करता है।
18. प्रत्यर्थी (प्रार्थी) द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित तथ्य व मौखिक रूप से उनके आधार पर दिये गये तर्क माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय दिनांक 27.08.2010 में साक्ष्यों के परीक्षण व निर्णय पर आपत्ति की है, जो निर्णय के पुनरावलोकन की मांग की परिभाषा में आता है।
19. उपरोक्त विवेचना के पश्चात निष्कर्ष है कि परिशोधन प्रार्थना-पत्र में लिखित Submission व बहस में प्रस्तुत किये गये तर्कों में निर्णय को गलत बताने, प्रकरण के दस्तावेजी साक्ष्यों पर आपत्ति करने के कारण प्रकरण में अभिलेख से प्रकट तथ्य या विधि की भूल होना नहीं पाया जाता है। निर्णय का पुनरावलोकन धारा 33 की परिधि व विषयक्षेत्र में नहीं आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2011) 29 टैक्स अपडेट 253, जो पैरा संख्या 14 में वर्णित है, के आलोक में परिशोधन प्रार्थना-पत्र को खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है।
20. परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी (प्रार्थी) का परिशोधन प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।
21. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी
18.09.2014
(मनोहर पुरी)
सदस्य